मध्यप्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

केडिया ग्रेट गैलन लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 921-922/2008)

28 फरवरी, 2017

[रंजन गोगोई और अशोक भूषण, जेजे.]

मध्य प्रदेश डिस्टिलरी नियम, 1995:

नियम 4 (41)-अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी को नोटिस-अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थापना पर अतिरिक्त व्यय के रूप में कुछ राशि की मांग-नियम 4(41) के अधिकारों को चुनौती दिए बिना रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मांग नोटिस को मनमाना और अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया-एकल न्यायाधीश ने हालांकि राय दी कि नियम 4 (41) एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम नियम बनाने की शक्ति से परे प्रतीत होता है, लेकिन इस संबंध में किसी भी अनुरोध के अभाव में, उस ओर से कोई आदेश नहीं दिया-रिट अपील खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः नियमों के अधिकार, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है-इस मुद्दे पर प्रवेश करने के लिए रिट याचिका में कोई पर्याप्त आधार नहीं रखा गया था कि क्या मांग मनमाना और अनुचित थी-हालाँकि, प्रतिवादी को मांग नोटिस के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी गई है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, रिट याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ नियमों को अधिकार से बाहर घोषित करते हुए आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थी। जवाबी हलफनामे में दिया गया बयान इंगित करता है कि नियमों की शक्तियों के संबंध में संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए कुछ विशिष्ट पीठ थी। यदि रिट याचिकाकर्ता ने नियमों के अधिकारों को चुनौती देने का इरादा किया था, तो उसे अधिकारों का फैसला करने के लिए रोस्टर वाली पीठ के समक्ष उचित राहत के लिए रिट याचिका दायर करनी थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता का कभी भी नियमों के अधिकारों को चुनौती देने का इरादा नहीं था। कुछ ऐसा जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता ने कभी इरादा या प्रार्थना नहीं की थी, इस अपील में नहीं देखा जा सकता है। [पैरा 40] (177-एफ-एच)

गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त (एए) और अन्य (2009) 14 एस. सी. सी. 338: [2009] 4 एस. सी. आर. 1183-विशिष्ट।

गिरिमल्लप्पा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एम और एम. आई. पी. और अन्य (2012) 11 एस. सी. सी. 548: [2012] 6 एस. सी. आर. 975-लागू नहीं हुआ।

2.1. जो लोग शराब बनाने या बेचने के लिए राज्य के विशेषाधिकार की मांग करने के लिए आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक नियमों और लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। विशेषाधिकार किसी पर भी नहीं लगाया जाता है, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों या पक्षों द्वारा इस तरह के अधिकार के निपटारे के लिए नीलामी में भाग लेकर या वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस तरह के विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्राप्त करके इसकी मांग की जाती है। [पैरा 22] [171-ई-एफ]

कूवरजी बी. भरूचा बनाम आबकारी आयुक्त, अजमेर ए. आई. आर. 1954 एस. सी. सी. 220: [1954) एस. सी. आर. 873; हर शंकर और अन्य बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान उपायुक्त और अन्य (1975) 1 एस. सी. सी. 737: (1975) 3 एस. सी. आर. 254-संदर्भित।

क्राउली बनाम क्रिस्टेंसन 34 एल ईडी 620-संदर्भित।

2.2. रिट याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि इस मुद्दे में प्रवेश करने के लिए रिट याचिका में कोई पर्याप्त आधार नहीं रखा गया था कि क्या मांग मनमाना और अनुचित है। मांग के विवरण से, यह और स्पष्ट है कि वर्ष 1996-97 की मांग में वेतन पर खर्च 4,36,897 रुपये के रूप में दिखाया गया था लेकिन उक्त वर्ष के राजस्व से संबंधित किसी भी आंकड़े का उल्लेख नहीं किया गया है, कि क्या आसवन संबंधित अवधि के दौरान काम कर सकता है और बिना कोई राजस्व होने के, प्रतिवादी पर वेतन पर खर्च कैसे निर्धारित किया जाता है, यह नहीं बताया गया है। [पैरा 52] [185-बी-सी]

2.3 तथापि, समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के समक्ष 23 मार्च, 1989 के मांग नोटिस के विरुद्ध प्रत्यर्थी को प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता देने में न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार संबंधित वर्षों से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों और वर्तमान मामले में प्रासंगिक अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करेगी। [पैरा 54] [186-बी]

आंध्र प्रदेश सरकार बनाम एम/एस आनाबेशाही वाइन एंड डिस्टिलरीज प्रा. लि. लिमिटेड (1988) 2 एस. सी. सी. 25-पर निर्भर।

बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य आदि 1970 (2) एस. सी. सी. 467: [1971] 1 एस. सी. आर. 844; एम/एस. - लिलासन्स ब्रुअरीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1992) 3 एस. सी. सी. 293: (1992) 2 एस. सी. आर. 595-लागू नहीं होता।

एम. पी. राज्य बनाम फर्म गापूलाल (1976) 1 एस. सी. सी. 791: [1976] 2 एस. सी. आर. 1041; आबकारी आयुक्त, यू. पी. बनाम राम कुमार (1976) 3 एस. सी. सी. 540: [1976] पूरक एस. सी. आर. 532; मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम के. सी. टी. ड्रिंक्स लिमिटेड (2003) 4 एस. सी. सी. 748: [2003] 2 एस. सी. आर. 574-संदर्भित।

प्रकरण विधि संदर्भ

[1992] 2 एस. सी. आर. 595	लागू नहीं किया गया	पैरा 3
[1954] एस. सी. आर. 873	संदर्भित	पैरा 17
[1975] 3 एस. सी. आर. 254	संदर्भित	पैरा 19
[2009] 4 एससीआर 1183	प्रतिष्ठित	पैरा 32
[2012] 6 एस. सी. आर. 975	लागू नहीं हुआ	पैरा 35
[1971] 1 एस. सी. आर. 844	लागू नहीं होता	पैरा 44
[1976] 2 एस. सी. आर. 1041	संदर्भित	पैरा 44
[1976) पूरक। एस. सी. आर. 532	संदर्भित	पैरा 44
[2003] 2 एस. सी. आर. 574	संदर्भित	पैरा 47

(1988) 2 धारा 25 पर निर्भर पैरा 48

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 921-922/2008

2000 के एल. पी. ए. संख्या 245 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के दिनांक 04.05.2000 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता अंकित के लाल (मिश्रा सौरभ के लिए)

जयंत कुमार मेहता, अभिजीत श्रीवास्तव, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा दिया गया।

1. ये अपीलें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.05.2000 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है और 13,24,189.50 रुपये की मांग की गई है। उत्तरदाताओं की आसवन पर राज्य सरकार के प्रतिष्ठान पर किए गए अतिरिक्त खर्च का दावा करते हुए निर्धारित किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रतिवादी केडिया ग्रेट गैलन लिमिटेड के पास शराब/स्पिरिट के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश डिस्टिलरी नियम, 1995 (इसके बाद नियम 1995 के रूप में संदर्भित) के तहत लाइसेंस था। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 23 मार्च, 1999 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 1995-96,1996-97 और 1997-98 से संबंधित मध्य प्रदेश डिस्टिलरी नियम, 1995 के नियम 4 (41) के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थापना पर अतिरिक्त व्यय के रूप में 13,24,189.50 रुपये की राशि की मांग की गई थी।।

3. उपरोक्त सूचना से व्यथित प्रत्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर की पीठ में 1999 की रिट याचिका संख्या 589 दायर की। प्रत्यर्थी ने अपनी रिट याचिका में मेसर्स लिलासन्स ब्रुअरीज (प्रा.) लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (1992) 3 एस. सी. सी. 293 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा, जिस मामले में मध्य प्रदेश शराब की भठ्ठी नियम, 1970 का नियम 22, जो राज्य को देय शुल्क के पांच प्रतिशत से अधिक अधिकारियों पर शराब की भठ्ठी शुल्क से वसूल करने का भी अधिकार देता है, को रद्द कर दिया गया था। प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका में अनुरोध किया कि नियम, 1995 का नियम 4 (41) भी अमान्य है, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के नियम के बल पर की गई मांग को निरस्त किया जा सकता है। रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा पैरा 7 में निम्नलिखित प्रार्थना की गई थीः

(i) आदेश अनुलग्नक/2 को निरस्त करते हुए अनिवार्य या जैसा उचित समझा गया कोई रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए और यह घोषित किया जाए कि डिस्टिलरी नियमों के नियम 4 (41) के तहत कोई मांग नहीं की जा सकती है।

(ii) ऐसी अन्य राहत को उचित समझा जाए।

(iii) इस याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाए।

4. राज्य द्वारा एक जवाबी-हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एम. पी. ब्रुअरीज नियम, 1970 का नियम 22 संदर्भ से बाहर है और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह मांग नियम, 1995 के नियम 4 (41) के तहत उठाई गई है।

5. राज्य ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा की गई मांग उचित है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यदि रिट याचिकाकर्ता नियम 4 (41) के अधिकारों को चुनौती देना चाहता है, तो इसे संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

6. एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मांग नोटिस को रद्द कर दिया। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि नियम 1995 का नियम 4 (41) मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के लिए नियम बनाने की शक्ति से परे प्रतीत होता है, हालाँकि चूंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जाता है, इसलिए इस संबंध में कोई आदेश इंदौर की पीठ द्वारा नियमों में पारित नहीं किया जा सकता है।

7. तथापि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि लिलासन्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय मांग सूचना अनुलग्नक पी. 2 को अमान्य बनाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि स्थापना शुल्क की मांग आसवन कारखानों की कुल आय का 150 प्रतिशत से अधिक है, जिसके आधार पर मांग मनमाना और अनुचित है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर, राज्य ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसे 06.09.2005 पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह विचारणीय नहीं है।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से व्यथित, ये अपीलें एम. पी. राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

10. हमने एम. पी. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकित कुमार लाल और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जयंत कुमार मेहता को सुना है।

11. अपील के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि मांग को अमान्य घोषित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय गलत है। यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने लिलासन्स मामले के फैसले पर भरोसा करते हुए मांग को अमान्य घोषित कर दिया था, जबकि लिलासन्स का फैसला एम. पी. ब्रुअरीज नियम-1970 के नियम 22 से संबंधित था, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित मांग को नियम 1995 के नियम 4 (41) के तहत उठाया गया था।

12. विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा बाद के कुछ निर्णयों में लिलासन्स के फैसले का पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका में, नियम 1995 के नियम 4 (41) को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, जो मांग पूरी तरह से नियम 4 (41) में शामिल थी, उसे रद्द नहीं किया जा सकता थाः यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 4 (41) अधिकार क्षेत्र के भीतर है और एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के अनुसार राज्य उपरोक्त मांग को पूरा करने का पूरी तरह से हकदार है। नियम 4 (41) के तहत उठाई गई मांग को एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 27 और 28 के तहत पूरी तरह से शामिल किया गया था।

विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि लाइसेंसधारी ने नियम 1995 के नियम 4 (41) के तहत निहित शर्तों के तहत लाइसेंस लिया है और वह मांग को चुनौती नहीं दे सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लाइसेंसधारी से स्थापना शुल्क की प्राप्ति के

प्रावधान विभिन्न राज्यों के विभिन्न उत्पाद शुल्क अधिनियमों में निहित हैं और इस न्यायालय द्वारा ऐसे प्रावधानों को अधिकार क्षेत्र के भीतर माना गया है।

13. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मेहता, अपीलार्थियों के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि लिलासन्स (उपरोक्त) का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है और मांग को रद्द करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से भरोसा किया गया था। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका में, नियम 4 (41) के अधिकारों को चुनौती देने वाले विशिष्ट आधार थे और केवल यह तथ्य कि रिट याचिका में कोई विशिष्ट राहत का दावा नहीं किया गया था, अप्रासंगिक है और यह न्यायालय नियम के अधिकारों की बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकता है, जो नियम लिलासन्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद निरस्त होने के लिए उत्तरदायी है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिष्ठान पर खर्च अर्जित राजस्व पर 150 प्रतिशत के रूप में दावा किया जाता है, जबकि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने प्रतिष्ठान शुल्क को पूरा करने के लिए राजस्व का 5 प्रतिशत विचार किया है, मांग अनुचित और मनमाना और अत्यधिक है। विद्वान वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैरा 9 पर भरोसा किया है जहां मांग को मनमाना और अनुचित माना गया है। विद्वान वकील ने आगे बताया कि मांग सूचना से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1996-97 में कोई राजस्व अर्जित नहीं हुआ था, जबकि 5 प्रतिशत से अधिक खर्च जो की 4,36,897 रुपये है, का दावा किया गया है।

14. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि राज्य ने स्वयं बाद के वर्षों में अपनी नीति बदल दी है और राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक की मांग को महसूस करने के बजाय, अब लाइसेंसधारी से एक निश्चित राशि ली जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि 2000 के एम. पी. अधिनियम संख्या 24 द्वारा एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम,

1995 में धारा 28-ए को शामिल करने से पहले इस तरह के शुल्कों को वसूल करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था, जो इंगित करता है कि शुल्क लाइसेंसधारी से वसूली योग्य नहीं थे।

15. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

16. शराब का व्यापार अनादिकाल से अस्तित्व में है। सभी सभ्य समाजों ने जल्द ही इस तरह के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करने की आवश्यकता को महसूस कर लिया था। एक प्रारंभिक निर्णय में, क्राउले बनाम क्रिस्टेंसन 34 एल. ई. डी. 620 में फील्ड, जे. ने उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की थींः "इसलिए, हर समय, प्रत्येक राज्य की अदालतों द्वारा इस तरह की शराब की बिक्री को विधायी विनियमन का उचित विषय माना गया है। न केवल एक गिलास शराब के निपटान से पहले टाइल सैलून के टाइल कीपर से लाइसेंस लिया जा सकता है, बल्कि उन व्यक्तियों के वर्ग के बारे में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिन्हें वे बेचे जा सकते हैं, और दिन के घंटे, और सप्ताह के दिन जिन पर सैलून खोले जा सकते हैं। उस रूप में उनकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो सकती है। यह सार्वजनिक औचित्य और सार्वजनिक नैतिकता का सवाल है, न कि संघीय कानून का। राज्य की पुलिस शक्ति व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है-इसकी बुराइयों को कम करने या इसे पूरी तरह से दबाने के लिए। इस प्रकार खुदरा रूप से मादक शराब बेचने का किसी नागरिक में कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है; यह राज्य के नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक का विशेषाधिकार नहीं है। चूँकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें समुदाय के लिए खतरा है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, या ऐसी शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है जो

इसकी बुराइयों को अधिकतम तक सीमित कर दें। विनियमन का तरीका और विस्तार शासी प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। वह प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों में निहित हो सकता है जो इसे चलाने की अनुमति के लिए आवेदनों को पारित करने और उस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति उचित समझते हैं। यह केवल विधायी इच्छा का मामला है।

17. इस न्यायालय ने कुवरजी बी. भरुचा बनाम आबकारी आयुक्त, अजमेर, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. सी. 220 में महाजन, सी. जे. के माध्यम से बोलते हुए, फील्ड जे. के उपरोक्त गद्य को मंजूरी देने के बाद, कहाः

> "इन टिप्पणियों में हमारी पूरी सहमति है और वे याचिकाओं की ओर से उठाए गए विवाद को पूरी तरह से नकारते हैं। विनियमन के प्रावधान शराब के सभी अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापार को विनियमित करने के लिए हैं और वैध हैं।"

18. महाजन, सी. जे. ने उपरोक्त मामले में आगे कहाः

> "इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के पास उन व्यापारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो अवैध या अनैतिक हैं या जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हैं। हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार या महिलाओं की तस्करी को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को निषेध लागू करने के रूप में अवैध नहीं माना जा सकता है, न कि केवल एक विनियमन।"

19. न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने, हर शंकर और अन्य बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान उपायुक्त और अन्य, (1975) 1 एस. सी. सी. 737 में एक संविधान पीठ

के माध्यम से बोलते हुए, इस न्यायालय की विभिन्न पिछली संविधान पीठों का उल्लेख करते हुए कहा, जो पैरा 45 और 47 में निम्नलिखित हैं:

> "45. नागेंद्र नाथ बोरा बनाम पहाड़ी प्रभाग और अपील आयुक्त, असम में, कूवरजी के मामले (उपरोक्त) और किदवई के मामले (उपरोक्त) में निर्णयों को एक संविधान पीठ द्वारा इस प्रस्ताव को निर्धारित करने के रूप में उद्धृत किया गया था कि एक नागरिक में शराब बेचने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं था और सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के संरक्षण और राजस्व बढ़ाने के लिए मादक शराब के सेवन पर नियंत्रण और प्रतिबंध आवश्यक थे।
>
> 47. पाँच संविधान पीठों के इन सर्वसम्मत निर्णयों में इस समस्या पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समान रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य के पास जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक व्यापारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, कि शराब के व्यापार की प्रकृति में उन्मूलन और बहिष्कार निहित है, कि किसी भी व्यक्ति को शराब का व्यापार करने का पूर्ण अधिकार नहीं है और शराब के सभी प्रकार के लेन-देन को, उनकी अंतर्निहित प्रकृति से, सभी सभ्य समुदायों द्वारा स्वयं एक वर्ग के रूप में माना गया है। यह तर्क कि नागरिक को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का प्राकृतिक या मौलिक अधिकार था, इस प्रकार खारिज कर दिया गया।"

20. उपरोक्त संविधान पीठ में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि शराब के अनन्य अधिकारों को बेचने का एक मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। पैरा 51 में निम्नलिखित कहा गया थाः

"…. कुवरजी के मामले (उपरोक्त) और कृष्ण कुमार नरूला के मामले (उपरोक्त) में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह देखा गया कि शराब बेचने के अनन्य अधिकार को बेचने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजस्व बढ़ाना था और चूंकि सरकार के पास अनन्य विशेषाधिकारों को बेचने की शक्ति थी, इसलिए यह तर्क देने का कोई आधार नहीं था कि विशेषाधिकारों का मालिक उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है यदि वह सोचता है कि प्रस्तावित मूल्य अपर्याप्त था। हेगड़े, जे. ने खंड पीठ के लिए बोलते हुए कहाः (एस. सी. सी. पृष्ठ 44, पैरा 13)

यह तथ्य कि सरकार विक्रेता थी, उन विशेषाधिकारों से निपटने के अपने विशेष अधिकार को स्वीकार करने के बाद कानूनी स्थिति को नहीं बदलता है। यदि सरकार उन विशेषाधिकारों की अनन्य स्वामी है, तो अनुच्छेद 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 14 पर निर्भरता अप्रासंगिक हो जाती है। यदि सरकार अपने मूल्यवान अधिकारों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करती है तो नागरिकों को सरकार से संबंधित संपत्तियों या अधिकारों में व्यापार करने या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है और न ही अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हो सकता है।"

21. मादक पदार्थों के निर्माण/बिक्री का विशेषाधिकार देने के लिए लिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रकृति पर विचार करते हुए, संविधान बेंच ने पैरा 59 में आगे कहाः

"लाइसेंसधारियों से ली जाने वाली राशि उचित रूप से तथाकथित शुल्क नहीं है और न ही वास्तव में एक कर है, बल्कि एक विशेषाधिकार की कीमत की प्रकृति में है, जिसे खरीदार को किसी भी व्यापार या व्यावसायिक लेनदेन में भुगतान करना पड़ता है।"

22. जो लोग शराब बनाने या बेचने के लिए राज्य के उपरोक्त विशेषाधिकार की मांग करने के लिए आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक नियमों और लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। विशेषाधिकार किसी पर भी नहीं लगाया जाता है, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों या पक्षों द्वारा इस तरह के अधिकार के निपटारे के लिए नीलामी में भाग लेकर या वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस तरह के विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्राप्त करके इसकी मांग की जाती है।

23. मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री से संबंधित विशेषाधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखने के बाद इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर पक्षियों की नज़र रखना प्रासंगिक है।

24. मादक शराब और मादक पदार्थों के आयात-निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए केंद्रीय प्रांत अधिनियम 1915 (एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 जिसे इसके बाद अधिनियम 1915 के रूप में संदर्भित किया गया है) अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम का चौथा अध्याय निर्माण, अधिकार और बिक्री से संबंधित है। धारा 13 में प्रावधान है कि प्राधिकरण के तहत और उस ओर से दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन होने के अलावा किसी भी मादक पदार्थ का निर्माण या संग्रह नहीं किया जाएगा। धारा 14 आसवन और गोदामों की स्थापना और लाइसेंस देने

से संबंधित है। धारा 18 निर्माण आदि के अधिकार को पट्टे पर देने की शक्ति से संबंधित है। धारा 18 (1) नीचे उद्धृत की गई है।

"18.1. राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए पट्टा दे सकती है, जो वह उचित समझे-

(ए) विनिर्माण का, या थोक या दोनों द्वारा आपूर्ति का, या

(बी) थोक या खुदरा द्वारा बिक्री का, या

(सी) विनिर्माण का या थोक द्वारा आपूर्ति का, या दोनों का, और खुदरा द्वारा बिक्री का कोई भी अधिकार।

[1964 के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19 द्वारा हटा दिया गया] कोई भी एक।" किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर शराब या मादक दवा।"

25. अध्याय V कर्तव्यों और शुल्कों से संबंधित है। धारा 25 (1) कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क से संबंधित है। धारा 25 (1) नीचे उद्धृत की गई है।

"25 (1). यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो चिकित्सा और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1955 की अनुसूची में कुछ समय के लिए निर्दिष्ट औषधीय और शौचालय की तैयारी के अलावा सभी उत्पाद शुल्क या जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। (1955 का सं. 16)-

(ए) आयातित; या

(बी) निर्यातित; या

(सी) परिवहन; या

(डी) धारा 13 के तहत दिए गए किसी लाइसेंस के तहत निर्मित, खेती या संग्रहित; या

(ई) इस अधिनियम के तहत स्थापित किसी आसवन या किसी आसवन या शराब बनाने के लाइसेंस का निर्माणः

बशर्ते कि राज्य सरकार के लिए किसी भी उत्पाद शुल्क से छूट देना वैध होगा, जिसके लिए वह इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो सकता है।"

26. धारा 27 पट्टों के अनुदान के लिए भुगतान से संबंधित है। धारा 27 इस प्रकार हैः

"इस अध्याय के तहत देय किसी भी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार धारा 18 के तहत किसी भी पट्टे के अनुदान के विचार में राशि का भुगतान स्वीकार कर सकती है।

27.2 उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात का अर्थ राज्य सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या लाइसेंस की मुद्रा के दौरान धारा 18 के तहत किसी पट्टे के अनुदान पर विचार करते हुए प्राप्त राशि को बढ़ाने या कम करने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा और राशि को बढ़ाने या कम करने की शक्ति में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले की तारीख से ऐसी वृद्धि या कमी को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी।"

27. अध्याय VI लाइसेंस, परमिट और पास से संबंधित है। धारा 28 इस प्रकार हैः

"28. अनुज्ञप्ति का प्रपत्र और शर्तें आदि।

(1). इस अधिनियम के तहत जारी किया गया प्रत्येक परमिट या पास या लाइसेंस ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, ऐसी अवधि के लिए ऐसे शुल्क के भुगतान पर जारी या प्रदान किया जाएगा और ऐसे रूप में होगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो निर्धारित किए जाएं।

(2). उप-धारा (1) के तहत निर्धारित शर्तों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसधारी को बिक्री के लिए अपनी दुकान के लिए निर्धारित देशी शराब या भारतीय निर्मित शराब की न्यूनतम मात्रा उठाने और शराब की मात्रा पर निर्धारित दर पर जुर्माना देने की आवश्यकता हो सकती है।

(3). उप-धारा (2) में विशेष रूप से गणना की गई उप-धारा (1) में निर्धारित किसी भी शर्त के तोड़ने या उल्लंघन पर निर्धारित दर पर जुर्माना अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपणीय और उससे वसूली योग्य होगा।"

28. धारा 62 राज्य की नियम बनाने की शक्ति है। उप-धारा (1) (एच), जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

"62 (1) (एच). प्राधिकरण को उस प्रपत्र द्वारा विहित करना, जिसमें नियम और शर्तें और जिसके अधीन कोई लाइसेंस, परमिट या

पास दिया जाएगा, और ऐसे नियमों द्वारा, अन्य मामलों के साथ-साथ -

(i) वह अवधि निर्धारित करें जिसके लिए कोई लाइसेंस, परमिट या पास लागू रहेगा,

(ii) किसी ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के संबंध में देय शुल्क का पैमाना या शुल्क निर्धारित करने का तरीका निर्धारित करें,

(iii) किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास के धारकों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि निर्धारित करें,

(iv) बनाए रखने के लिए खातों और लाइसेंस धारकों द्वारा जमा किए जाने वाले विवरणों को निर्धारित करें, और

(v) साझेदारी या लाइसेंस के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित करें।"

29. उपरोक्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य ने मध्य प्रदेश आसवन नियम, 1995 नाम का नियम बनाया है। धारा 4 (41), जो वर्तमान मामले में शामिल है, इस प्रकार हैः

"4 (41) यदि राज्य सरकार द्वारा किसी आसवनगृह की स्थापना पर किया गया व्यय, उससे स्पिरिट के मुद्दे पर अर्जित राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक है, तो निर्यात शुल्क या किसी अन्य शुल्क से, उपरोक्त पांच प्रतिशत से अधिक राशि, आसवनगृह से प्राप्त की जाएगी।"

30. वैधानिक योजना पर ध्यान देने के बाद, अब हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा जिस पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या इस न्यायालय को 1995 के नियमों के नियम 4 (41) के अधिकारों की जांच करने की आवश्यकता है, जबकि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका में, नियम 1995 के नियम 4 (41) को निरस्त करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

31. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में और आधारों में, नियम 4 (41) को चुनौती दी गई थी और नियम 4 (41) को अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए एक विशिष्ट राहत का दावा करने में केवल चूक नियम 4 (41) की शक्तियों की जांच और आवश्यक घोषणा देने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने रिट याचिका के पैरा 9 का उल्लेख किया है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित हैः

> "कि मेसर्स लीला संस ब्रुअरी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए डिस्टिलरी नियमों का नियम 4(41) भी अमान्य है। नतीजतन, इस तरह के नियम के बल पर कोई मांग नहीं की जा सकती है, इसलिए अनुलग्नक/1 में की गई मांग को रद्द किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुसार शराब बनाने के नियमों का पुराना नियम 22 अधिकार से बाहर है और परिणामस्वरूप डिस्टिलरी नियमों का नियम 4 (41) गैर-प्रभावी है। इसलिए नियम 4 (41) को निरस्त करने के लिए अलग से राहत लेने की आवश्यकता नहीं है।"

32. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त (ए. ए.) और अन्य (2009) 14 एस. सी. सी. 338 में इस न्यायालय के फैसले

पर भी भरोसा किया है, इस प्रस्ताव के समर्थन में कि जब किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि वह अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त है, तो यह तथ्य कि कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया है, महत्वहीन है। उपरोक्त मामले में, पैरा 12 और पैरा 13 में निम्नलिखित माना गया थाः

> "12. यह सच है कि अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिका में एक विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 21-1-2006 अधिकार से बाहर थी या अन्यथा अवैध थी, लेकिन जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है, उस संबंध में एक विशिष्ट आधार लिया गया था।
>
> 13. अन्यथा भी, हमारी राय में, यह प्रश्न कि क्या उक्त अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है या पूर्वव्यापी संचालन एक क्षेत्राधिकार तथ्य होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए था क्योंकि यह सर्वविदित है कि जब किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि वह अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त है, तो वैकल्पिक उपाय एक बाधा नहीं हो सकता है। (व्हर्लपूल कॉर्प. बनाम ट्रेड मार्क्स और मुमताज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के पंजीयक बनाम कुलपति देखें।)

33. उपरोक्त निर्णय का अनुपात पैरा 13 में निहित है। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जब सांविधिक प्राधिकारी के किसी आदेश पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि वह अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त है तो वैकल्पिक उपचार

कोई बाधा नहीं थी और क्या 21.1.2006 दिनांकित अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है या पूर्वव्यापी संचालन एक अधिकार क्षेत्र होने के कारण, उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्धारण करना चाहिए था।

34. वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां मांग का नोटिस जारी करने वाले जिला आबकारी अधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव हो और न ही पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी संचालन का कोई मुद्दा हो। उपरोक्त मामला किसी भी तरह से उत्तरदाताओं की मदद नहीं करता है।

35. प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा किया गया दूसरा मामला गिरिमल्लप्पा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एम और एम. आई. पी. और दूसरा (2012) 11 एस. सी. सी. 548 है।

36. उपरोक्त मामले में, संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ; जिला न्यायाधीश के समक्ष एक भूमि अधिग्रहण अपील दायर की गई थी, जिसमें मुआवजे को 24000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बढ़ाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में कोई विशिष्ट राशि की मांग नहीं की गई थी।

37. जिला न्यायाधीश ने प्रति एकड़ Rs.24000 के दावे को स्वीकार कर लिया, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की अपील दायर की गई थी, इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय को मुआवजा देने में पर्याप्त न्याय पर तकनीकीता को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी। पैरा 13 और 14 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

> "13. यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें किसी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सके कि वह जारी करने वाले प्राधिकारी की

क्षमता के अभाव के लिए अमान्य है और उसे चुनौती देने वाले उचित आधारों सहित उचित अभिवचन लिए गए हैं, लेकिन उक्त आदेश को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आदेश की जांच उसमें लागू वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद ही की जा सकती है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि आदेश अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त है।

14. यदि याचिकाकर्ता मामले के बारे में गंभीर था, तो वह अपील के ज्ञापन में संशोधन कर सकता था और उस आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता था जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरचरण बनाम हरियाणा राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था। इस याचिका में उल्लिखित तथ्य एक पूरी तरह से अलग तस्वीर को दर्शाते हैं और यह एक धारणा देता है जैसे कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे को नहीं बढ़ाया था, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत की फीस के भुगतान की कमी के लिए मांग की गई थी, जिसे वह धन की कमी के कारण भुगतान नहीं कर सकता था।"

उपरोक्त मामला भी किसी भी तरह से उत्तरदाताओं की मदद नहीं करता है।

38. एक अन्य कारण है जिसके कारण, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की उपरोक्त प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिका के पैरा 9 में, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मेसर्स लिलासन के फैसले को देखते हुए 1995 के नियमों का नियम 4 (41) अमान्य है। लेकिन; रिट याचिका में कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं थी। नियम 4 (41) को अधिकारातीत

घोषित करने वाली विशिष्ट प्रार्थना नहीं करने का कारण कोई चूक या निरीक्षण नहीं था। अभिलेख पर अभिवचन उपरोक्त कारण का खुलासा करते हैं. पैरा 2 में अनुलग्नक पी-3 के रूप में अभिलेख पर लाई गई रिट याचिका के लिए राज्य की ओर से दायर जवाबी-शपथ पत्र में राज्य द्वारा निम्नलिखित बयान दिया गया हैः

> "प्रत्यर्थी द्वारा की गई मांग उचित है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता नियम 4 (41) के अधिकारों को चुनौती देना चाहता है, तो इसे केवल संवैधानिक पीठ के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।"

39. लर्नड सिंगल जज ने रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए पैरा 7 में भी निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः

> "उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, वर्तमान नियम, 1995 का नियम 4 (41) भी एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर और राज्य की नियम बनाने की शक्ति से परे प्रतीत होता है। हालाँकि, चूंकि याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है और इस संबंध में कोई आदेश इंदौर पीठ द्वारा नियमों के तहत पारित नहीं किया जा सकता है। मैं इस प्रश्न को केवल यहाँ छोड़ता हूँ. हालाँकि, लिलेसन और केडिया डिस्टिलरीज़ (उपरोक्त) में निर्णयों का अनुपात मांग सूचना (अनुलग्नक पी. 2) को शून्य बनाता है।"

40. इस प्रकार उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, इंदौर में रिट याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ नियमों को अधिकार से बाहर घोषित करते हुए आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थी। जवाबी हलफनामे में दिया

गया बयान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इंगित करता है कि नियमों के अधिकारों के संबंध में संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए कुछ विशिष्ट पीठ थी। इस प्रकार यदि रिट याचिकाकर्ता ने नियमों के अधिकारों को चुनौती देने का इरादा किया था, तो उसे अधिकारों का फैसला करने के लिए रोस्टर वाली पीठ के समक्ष उचित राहत के लिए रिट याचिका दायर करनी थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता का कभी भी नियमों के अधिकारों को चुनौती देने का इरादा नहीं था; जो कि ऊपर बताए गए कारणों से स्पष्ट है; इस प्रकार हमारी सुविचारित राय है कि जिस चीज़ के लिए रिट याचिकाकर्ता ने कभी इरादा या प्रार्थना नहीं की थी, उस पर इस अपील में विचार नहीं किया जा सकता है।

41. विद्वत एकल न्यायाधीश ने विवादित निर्णय में मेसर्स लिलेसन (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए मांग को खारिज कर दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि लिलासन और केडिया डिस्टिलरीज में निर्णय का अनुपात मांग सूचना को अमान्य बनाता है। लिलासन्स के निर्णय पर विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, इसलिए उक्त निर्णय पर कुछ विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है।

42. लिलासन्स के मामले में, एम. पी. शराब बनाने के नियम 1970 के नियम 22 पर सवाल उठाया गया था। उपरोक्त नियमों के नियम 22 को निर्णय के पैरा 2 में निकाला गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

> "2. मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की धारा 62 के तहत बनाए गए मध्य प्रदेश शराब बनाने के नियम, 1970 के नियम 22 पर सवाल उठाए गए हैं। वह नियम कहता हैः

"22. शराब बनाने की फैक्ट्री के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आबकारी आयुक्त-प्रत्येक शराब बनाने की फैक्ट्री को आबकारी आयुक्त द्वारा शराब बनाने की फैक्ट्री के प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए एक आबकारी निरीक्षक के प्रभार में रखा जाएगा। आबकारी आयुक्त आगे आबकारी विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह शराब बनाने के कारखानों के प्रभार के लिए उपयुक्त समझे। ऐसे सभी अधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा; बशर्ते कि जब राज्य के भीतर शराब बनाने वाले कारखाने से जिलों को दिए जाने वाले मुद्दों पर वार्षिक शुल्क देय शुल्क के पांच प्रतिशत से अधिक हो, तो अतिरिक्त शुल्क शराब बनाने वाले से वसूल किया जाएगा।"

43. यह न्यायालय नियम 22 और एम. पी. आबकारी अधिनियम, 1915, धारा 18,25,27 और 28 के प्रावधानों को नोटिस करने के बाद इसके निष्कर्ष को पैराग्राफ 8 और 9 में दर्ज किया है जो नीचे दिए गए हैंः

"8. अब सवाल यह है कि क्या मांग एक और शुल्क है और इसलिए एक और कर या क्या यह अधिकार हस्तांतरण के लिए एक और शुल्क या विचार है। बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में, इस न्यायालय को धारा 27 और 62 (2) (एच) सहित अधिनियम के कुछ प्रावधानों की जांच करने का अवसर मिला था। तत्कालीन अपीलकर्ताओं के लाइसेंस की शर्तों के तहत उन्हें शराब की मात्रा पर उत्पाद शुल्क का अनिवार्य भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसकी वे डिलीवरी लेने में विफल रहे, क्योंकि उन शर्तों ने शराब

की न्यूनतम मात्रा निर्धारित की थी जिसे उन्हें सरकार से खरीदना था। उन्हें इस तरह के दायित्व से मुक्त करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः (एस. सी. सी. p.471, पैरा 12)

"न तो धारा 25 और न ही धारा 26 और न ही धारा 27 और न ही धारा 62 (1) और न ही धारा 62 (2) के खंड (डी) और (एच) नियम बनाने वाले प्राधिकरण को राज्य सरकार को उन उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार देते हैं जो धारा 13 के तहत दिए गए किसी भी लाइसेंस के तहत आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, खेती या एकत्र नहीं की गई हैं या अधिनियम के तहत किसी भी आसवन या किसी भी आसवन या शराब बनाने की दुकान में निर्मित नहीं की गई हैं। विधायिका ने केवल उन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया है जो धारा 25 के दायरे में आती हैं। नियम बनाने वाले प्राधिकरण को किसी भी ऐसी वस्तु पर शुल्क लगाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो धारा 25 के दायरे में नहीं आती है। इसलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी कोई शक्ति उस प्राधिकरण को प्रदान की जा सकती है। काफी स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने शराब पर शुल्क लगाने का इरादा किया जिसे ठेकेदार उठाने में विफल रहे। ऐसा करने में यह एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास था जो उसके पास नहीं थी।

किसी भी उप-कानून या नियम या विनियमन द्वारा कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वह क़ानून जिसके तहत अधीनस्थ कानून बनाया गया है, विशेष रूप से लागू करने को

अधिकृत नहीं करता है, भले ही यह माना जाता है कि कर लगाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंपी जा सकती है। कानून द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्ति के आधार का नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। एक नियम बनाने वाले प्राधिकरण के पास कोई पूर्ण शक्ति नहीं होती है। इसे दी गई शक्ति की सीमाओं के भीतर काम करना होगा।

बनर्जी मामले में अनुपात का पालन मध्य प्रदेश राज्य बनाम फर्म गप्पूलाल में किया गया था और फिर उत्तर प्रदेश के एक मामले में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम राम कुमार में किया गया था। अब यदि शराब बनाने के नियमों के नियम 22 के तहत कार्रवाई धारा 25 के तहत अधिकृत नहीं है और इसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में बनाया जा रहा है, तो पूर्व उद्धृत तीन मामले मांग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। लेकिन यदि यह लाइसेंस के अनुदान के लिए विचार के रूप में धारा 27 के तहत एक अतिरिक्त भुगतान है, या लाइसेंस की एक अतिरिक्त शुल्क या शर्त है, जैसा कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा तर्क दिया गया है, तो इसे बनाए रखना पड़ सकता है। इस स्तर पर पन्ना लाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा जिसमें लाइसेंस में उल्लिखित गारंटीकृत या निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए लाइसेंसधारी का संविदात्मक दायित्व उसके द्वारा रखी गई शराब की मात्रा पर निर्भर नहीं माना गया था और लाइसेंस के तहत अप्रचलित शराब पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लिया गया था या नहीं लिया गया था। उपर्युक्त मामला राज्य के बचाव को आगे नहीं बढ़ा

सकता है क्योंकि तत्काल लाइसेंस में कोई एकमुश्त भुगतान निर्धारित नहीं है। लाइसेंस में केवल यह उल्लेख है कि लाइसेंसधारी शराब बनाने के नियमों से बंधा होगा। उस स्थिति में उच्च न्यायालय ने धारा 62 (2) (एच) और 28 पर भरोसा किया जब यह पता चला कि शराब बनाने के कारखानों के नियंत्रण के लिए तैनात अधिकारियों के वेतन के संबंध में शुल्क की वसूली के लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हम नियम 22 के बाद के भाग का विश्लेषण करते हैं, तो निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैः

(i) ऐसे सभी अधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा; (सरकार की जिम्मेदारी है)

(ii) यदि राज्य के भीतर के जिलों को शराब बनाने वाले कारखाने से किए गए मुद्दे पर देय शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक वार्षिक शुल्क नहीं है, तो शराब बनाने वाले से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है;

(iii) शुल्क का 5 प्रतिशत इतना माना गया है जिससे ऐसे अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को प्रतिपूर्ति की जा सके; और

(iv) यदि वार्षिक शुल्क देय शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो शराब बनाने वाले से अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा, यानी ऐसे सभी अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए।

9. एकत्रित उत्पाद शुल्क राज्य के खजाने में जाता है। अधिकारियों का वेतन राज्य के खजाने से आना पड़ता है। देय शुल्क का पाँच प्रतिशत ऐसे अधिकारियों के वेतन को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसे सरकार, लेकिन नियम के लिए, अन्यथा पूरा करती है। नियम का यह हिस्सा विशुद्ध रूप से सरकार और उसके अधिकारियों के बीच आंतरिक है। अनुज्ञप्तिधारी इस बात को लेकर कम से कम चिंतित है कि देय उत्पाद शुल्क को कैसे विनियोजित किया जाएगा। यह केवल एक कमी के मामले में होता है जब शराब बनाने वाले से अतिरिक्त प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि वह प्रभावित होता है। अब यह अधिकता क्या है? यह स्पष्ट रूप से वह राशि है जो देय शुल्क से कम है। दूसरे शब्दों में यह शराब बनाने वाले के लिए हैः "आपने पर्याप्त मात्रा में बीयर नहीं उठाई है और उन्हें राज्य के भीतर के जिलों में नहीं भेजा है। इस प्रकार राज्य ने पर्याप्त उत्पाद शुल्क अर्जित नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप इसके 5 प्रतिशत में कमी आई है। यह अधिकारियों के वार्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं जाता है। इसलिए आप सामान उठाए बिना कमी को पूरा करते हैं। इसलिए, कमी एक ही रंग और सामग्री का हिस्सा है। एक पल के लिए यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि जब कमी होती है, तो मांग "अतिरिक्त शुल्क या विचार" की होती है, न कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की। नियम की भाषा से यह स्पष्ट है कि अधिकारियों के वेतन को पूरा करने के लिए अपेक्षित पांच प्रतिशत से कम लगने वाले उत्पाद शुल्क की स्थिति में उससे भुगतान नहीं किया जा सकता है, राज्य को भुगतान करने के लिए सभी समान है।

यह उपाय राज्य को शुल्कों की भरपाई करने के लिए उस सीमा तक देय शुल्क के बराबर राशि की मांग करने के लिए जाता है, बिना किसी उत्पाद शुल्क को हटाए। इस समझ के आधार पर मांग को बनर्जी मामले, फर्म गप्पूलाल मामले और राम कुमार मामले के अनुपात से नुकसान हुआ है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। नियम 22 उस हद तक अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और राज्य की नियम बनाने की शक्ति से परे है।"

44. लिलासन्स के मामले (उपरोक्त) के निर्णय का आधार बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य आदि, 1970 (2) एस. सी. सी. 467 में निर्णय था। बिमल चंद्र बनर्जी के मामले में इस न्यायालय को मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के प्रावधानों की जांच करने का अवसर मिला था, जिसमें धारा 27 और 62 (2) (एच) शामिल थे। फैसले के पैराग्राफ 8 से, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह स्पष्ट है कि शराब की मात्रा पर उत्पाद शुल्क का अनिवार्य भुगतान, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा नहीं उठाया जा सका था, अवैध माना गया था। बिमल चंद्र बनर्जी के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण को किसी भी ऐसी वस्तु पर शुल्क लगाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो धारा 25 के दायरे में नहीं आती है और विधानमंडल ने केवल उन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया है जो धारा 25 के दायरे में आती हैं, अर्थात वे उत्पाद शुल्क जो किसी भी लाइसेंस के तहत निर्मित की गई हैं। बनर्जी के मामले को संदर्भित करने के बाद, लिलासन्स ने दो अन्य निर्णयों पर भरोसा किया, अर्थात् स्टेट ऑफ एमपी बनाम फर्म गापूलाल, (1976) 1 एससीसी 791 और आबकारी आयुक्त, यू. पी. बनाम राम कुमार, (1976) 3 एससीसी 540। उपरोक्त दोनों मामलों में एक ही प्रस्ताव रखा गया था।

45. बनर्जी के मामले में फैसला 19 अगस्त, 1970 को दिया गया था। 1995 के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 6 द्वारा धारा 28 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा विशिष्ट प्रावधान के तहत लाइसेंसधारक को बिक्री के लिए उठाने की आवश्यकता होती है, उसकी दुकान के लिए देशी स्पिरिट या भारतीय निर्मित शराब की न्यूनतम मात्रा निर्धारित की जाती है और निर्धारित दर पर जुर्माने का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 की योजना को 1995 के उपरोक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, बनर्जी के मामले के आधार को ही रद्द कर दिया गया है और बदली हुई वैधानिक योजना को देखते हुए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिलेसन्स मामले में निर्णय 21 अप्रैल, 1992 को दिया गया था, जो 1995 के एम. पी. अधिनियम संख्या 6 द्वारा धारा 28 में उपरोक्त संशोधन से पहले है। लिलासन्स के फैसले के पैराग्राफ 9 में यह माना गया था कि जब बीयर की पर्याप्त मात्रा को उठाने में कमी आती है, तो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मांग की जाती है जिसकी अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 10 में लिलासन्स मामले में धारा 27 और 28 का भी उल्लेख किया गया था। पैराग्राफ 10 नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "10. अब धारा 62 (2) (एच) और धारा 28 के सुझाए गए व्यापक आयाम और लाइसेंस की शर्त के संबंध में, हमें बस इतना कहना है कि हालांकि धारा 28 के तहत लाइसेंस निर्धारित प्रपत्रों पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और ऐसे विवरण वाले लाइसेंस जो राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है आदि, यह शक्ति भले ही व्यापक रूप से अभी भी अपने ढांचे के भीतर सीमित है और किसी भी स्थिति में अधिनियम की मंजूरी के बिना नियम के माध्यम से कर या उत्पाद शुल्क लगाने या लगाने की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती है। जैसा कि हमने पहले विश्लेषण किया

है, घटनाओं की आकस्मिकता पर पूछा गया भुगतान, धारा 28 के दायरे में आने के लिए शुल्क के रूप में भाग नहीं ले सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो धारा 62 (2) (एच) का समर्थन निर्जंतुक है। धारा 27 से सहायता लेने का भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इसमें परिकल्पित अतिरिक्त भुगतान भी देय शुल्क के अतिरिक्त और धारा 18 के तहत किसी भी पट्टे के अनुदान के लिए एक आंशिक विचार के रूप में भुगतान है। धारा 27 में परिकल्पित अतिरिक्त प्रतिफल उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त है। जिस तरह से हमने नियम 22 का विश्लेषण किया है, धारा 27 की शर्तें स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं जाती हैं।"

46. धारा 28, जैसा कि ऊपर देखा गया है, को 1995 के एम. पी. अधिनियम संख्या 6 द्वारा संशोधित किया गया है और उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 में संशोधन के बाद, धारा 28 की सामग्री को पूरी तरह से बदल दिया गया है और यह पता लगाने के लिए धारा 28 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि क्या नियम 4 (41) के तहत मांग धारा 28 के दायरे से बाहर है।

47. एम. पी. राज्य और अन्य बनाम के. सी. टी. ड्रिंक्स लिमिटेड, (2003) 4 एस. सी. सी. 748 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को एम. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915, धारा 27 पर विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में लाइसेंस की शर्त 8 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, लाइसेंसधारी के परिसर में तैनात उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षी कर्मचारियों की पूरी लागत का भुगतान करेगा। हालाँकि, लिलासन्स के फैसले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था,

लेकिन, हालाँकि, इस न्यायालय ने लाइसेंस के खंड 8 को बरकरार रखा और पैराग्राफ 7 और 11 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

> "7. धारा 18 और 27 को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार लाइसेंस विलेख में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अधिनियम के तहत देय किसी भी शुल्क के अलावा एकमुश्त किसी भी पट्टे के अनुदान के विचार में राशि का भुगतान स्वीकार करने की हकदार है। लाइसेंस की शर्त 8 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी के. सी. टी. पेय, मंडीदीप, जिला रायसेन के परिसर में तैनात उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षी कर्मचारियों की पूरी लागत का भुगतान करेगा।
>
> 11. उपरोक्त तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार को प्रतिवादी के परिसर में तैनात पर्यवेक्षी कर्मचारियों की वास्तविक लागत की वसूली करने के लिए सशक्त करने वाली शर्त को किसी भी तरह से अवैध या अधिकार से परे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह वह कीमत या प्रतिफल है जो सरकार अपने विशेषाधिकार को छोड़ने और लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसधारक से लेती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता है।"

48. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मेसर्स आनाबेशाही वाइन एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, (1988) 2 एस. सी. सी. 25 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा रखा है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने माना कि स्थापना शुल्क के संबंध में मांग वैध और कानूनी थी। 49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने में विफल हैं कि लिलासन्स के मामले

में इस न्यायालय के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा मांग को अमान्य घोषित करने के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है।

50. इस मामले का एक और पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी से जो मांग का दावा किया गया है वह 3 साल से संबंधित है। 23 मार्च, 1999 के नोटिस में मांग के विवरण का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैंः

वर्ष	राजस्व (रु.)	राजस्व का 5%(रु.)	सैलरी पर खर्च (रु.)	5% से ज्यादा खर्च
1995-96	308250	15412.50	3,91,956/-	3,76,543.50
1996-97	-	-	4,36,897	436897
1997-98	555000	27,750.00	5,38,499/-	510749
			कुल	13,24,189.50

51. उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 8 में मांग के विवरण पर ध्यान दिया है और मांग को मनमाना और अनुचित भी माना है। पैराग्राफ 8 में, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा हैः

> "8. मांग मनमाना और अनुचित है, अन्यथा भी। यह तथ्य कि 5 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिष्ठान शुल्क राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि प्रतिष्ठान पर खर्च उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। बिहार डिस्टिलरीज (ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1208) में एक अन्य निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य डिस्टिलरी में तैनात कर्मचारियों की लागत का भुगतान करने के लिए उचित नियामक शुल्क लगाने का हकदार होगा। हालाँकि,

आक्षेपित सूचना (अनुलग्नक पी/2) को पढ़ना महत्वपूर्ण है। संबंधित वर्षों 1995-96 से 1997-98 के दौरान आसवन की कुल आय रु 8,63,250- दिखाई गयी है। इसके विपरीत, 5 प्रतिशत से अधिक स्थापना शुल्क की मांग Rs.13,24,189.50 पर दिखाई गई है। प्रतिष्ठान में दिखाए गए कुल खर्च आसवन की कुल आय के 150% से अधिक हैं। इसके बावजूद यह मांग मनमाना और अनुचित है। इसके बावजूद, मांग मनमाना और अनुचित है; नियम 4 (41) की वैधता के सवाल को दरकिनार करते हुए इसे इस आधार पर खारिज किया जा सकता है।"

52. उच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिष्ठान शुल्क राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि प्रतिष्ठान पर खर्च उचित सीमा के भीतर होना चाहिए और मांग मनमाना और अनुचित प्रतीत होती है। लेकिन रिट याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि इस मुद्दे में प्रवेश करने के लिए रिट याचिका में कोई पर्याप्त आधार नहीं रखा गया था कि क्या मांग मनमाना और अनुचित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मांग के विवरण से यह और स्पष्ट है कि वर्ष की मांग में वेतन पर व्यय रुपये के रूप में दिखाया गया था-लेकिन उक्त वर्ष के राजस्व से संबंधित कोई आंकड़ा उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या आसवन संबंधित अवधि के दौरान काम कर सकता है और बिना किसी राजस्व के प्रतिवादी पर वेतन पर व्यय कैसे निर्धारित किया जाता है, यह समझाया नहीं गया है।

53. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य ने नियम 4(41) में निहित सांविधिक योजना को छोड़ दिया है और बाद में लाइसेंस शुल्क में शामिल स्थापना शुल्क की राशि निर्धारित की है। हालाँकि, राज्य के

विद्वान वकील ने प्रतिवादी के विद्वान वकील के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण का खंडन किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने धारा 28-ए का भी उल्लेख किया है, जिसे मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 2000 का अधिनियम संख्या 24, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

> "धारा 28-ए. पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान-राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में निर्देश दे सकती है कि किसी भी मादक, विकृत स्पिरिट तैयार या भांग के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण, बिक्री, खरीद, उपयोग, संग्रह या खेती ऐसे आबकारी कर्मचारियों की देखरेख में हो जो आबकारी आयुक्त इस संबंध में नियुक्त करना उचित समझे और यह कि मादक या विकृत स्पिरिट तैयार करने का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण, खरीद, उपयोग, संग्रह या खेती करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लगाया जाए।
>
> बशर्ते कि राज्य सरकार किसी भी वर्ग के व्यक्ति या किसी भी संस्थान को ऐसे शुल्क के पूरे या किसी भी हिस्से का भुगतान करने से छूट दे सकती है।"

54. धारा 28-ए उस प्रासंगिक अवधि के दौरान अस्तित्व में नहीं है जिसके लिए मांग की गई है, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, धारा 28-ए के प्रभाव और परिणाम पर विचार किया जाए। हालाँकि, समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य के समक्ष 23 मार्च, 1989 के मांग नोटिस के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिवादी

को स्वतंत्रता देने में न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार संबंधित वर्षों से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों और वर्तमान मामले में प्रासंगिक अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करेगी। यदि आज से चार सप्ताह के भीतर ऐसा अभ्यावेदन अपीलार्थी संख्या 2 को प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य अभ्यावेदन पर विचार करेगा और शीघ्रता से उचित निर्णय लेगा। यह बिना कहे चला जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय के परिणामस्वरूप आगे के कदम उठाए जाएंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है।

55. नतीजतन, उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.05.2000 के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।